<u>मूल हिंदी में</u>

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3410
13.03.2020 को उत्तर के लिए

हरियाणा में वन क्षेत्र

3410. श्री संजय भाटिया :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास हरियाणा विशेष रूप से करनाल में वन क्षेत्र के विस्तार के लिए कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को वन क्षेत्र के विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार के पास बड़े पैमाने पर हरियाणा में वृक्षारोपण अभियान चलाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग) राष्ट्रीय वन नीति (एनएफपी), 1988 के तहत देश में कुल वन भूमि का न्यूनतम एक-तिहाई हिस्सा वन या वृक्षावरण के अंतर्गत होने की परिकल्पना की गई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने हरियाणा सहित देश में वनावरण को बढ़ाने और उसमें सुधार हेतु कई पहलें की हैं। इसमें केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें जैसे राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन और वन्यजीव पर्यावासों का विकास शामिल हैं। प्रातिपूरक वनीकरण निधि नियमावली, 2018 भी वनों में सहायित प्राकृतिक पुनरूद्धभवन, कृत्रिम पुनरूद्धभवन और जंगल विज्ञान संचालनों को शुरू करने का प्रावधान करती है, जो वनावरण को बढ़ाने और उसमें सुधार हेतु अपना योगदान देती है। वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान हरियाणा को तदर्थ काम्पा द्वारा विभिन्न कार्यकलापों को शुरू करने के लिए क्रमश: 80.00 करोड़ रूपए और 144.20 करोड़ रूपए जारी किए गए थे। इसके अलावा, भारत सरकार ने अगस्त, 2019 में हरियाणा को राष्ट्रीय निधि से राज्य के हिस्से के रूप में, प्रतिपूरक निधि अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत वनीकरण सहित विभिन्न कार्यकलापों को शुरू करने हेतु 1282.65 करोड़ की राशि आवंटित की है।

भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के विभिन्न कार्यक्रमों/वित्त पोषित स्रोतों के तहत जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी स्कीम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और राज्यो / संघ राज्य क्षेत्रों की स्कीमों / योजनाओं के तहत भी और कार्पोरेट-निकायों, सामाजिक संस्थानों, सिविल सोसाइटी / एनजीओ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा गैर-वन क्षेत्रों में वनीकरण और वृक्षावरण कार्यकलाप शुरू किए जा रहे हैं।

हरियाणा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, क्रमश: वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में क्रमश: 1.67 करोड़, 1.34 करोड़ और 98.53 लाख नन्हें पौधे लगाए गए।

*****